भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3074
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान

3074. श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री रामप्रीत मंडलः
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण को सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए 'पूर्वोदय' योजना के अंतर्गत बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त संस्थान को कार्यशील बनाने के लिए अब तक की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त संस्थान किस जिले/स्थान पर स्थापित किया जा रहा है और इसके स्थल की पहचान और अन्य स्वीकृतियों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए अब तक स्वीकृत, आवंटित और खर्च की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त संस्थान की स्थापना के लिए समय-सीमा का ब्यौरा क्या है और उसमें हुई वर्तमान प्रगति, प्रस्तावित शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं, उससे रोजगार सृजन की संभावना तथा बिहार सहित देश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को होने वाले संभावित लाभ क्या हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग): पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ़्टेम) की स्थापना हेतु कदम उठाए गए हैं। बिहार राज्य सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को संस्थान की स्थापना के लिए बिहार के वैशाली जिले में राजापाकर (जाफरपट्टी) में 100 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के लिए 'सैद्धांतिक' स्वीकृति प्रदान की है। बिहार अवसंरचना विकास प्राधिकरण को निफ़्टेम के लिए भूमि के उपयुक्त भू-खंड की पहचान करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(घ): अब तक, इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा कोई निधि आवंटित नहीं की गई है और न ही कोई व्यय किया गया है।

(ङ): बिहार में निफ़्टेम की स्थापना की समय-सीमा राज्य सरकार द्वारा भूमि के औपचारिक हस्तांतरण और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की स्वीकृति पर निर्भर है, जिनमें से दोनों प्रक्रियाएँ अभी पूरी नहीं हुई हैं। प्रस्तावित संस्थान की स्थापना से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, मूल्य संवर्धन और इनक्यूबेशन सहायता को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे तथा बिहार और पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को समग्र रूप से मजबूती मिलेगी।

****